Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

मध्यप्रदेश में मेक इन इंडिया से विपणन चुनौतियों को कम करते हुये आत्मनिर्भर व्यापार की बढ़ती संभावनाएँ

शिवालिका सोहगौरा, डॉ. एम. यू. सिद्दीकी

प्राध्यापक वाणिज्य महाविद्यालय, बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.)

Article Info

Volume 5, Issue 2

Page Number : 97-100

Publication Issue :

March-April-2022

Article History

Received : 01 March 2022

Published : 17 March 2022

सारांश :–

भारत की वर्तमान पारिस्थितियों में covid 19 के कारण अर्थव्यवस्था को Vocal for local के अन्तर्गत एवं मेक इन इंडिया के अन्तर्गत भारत के उद्योगों में उत्पादन वृद्धि करके विदेशी व्यापार की वस्तुओं को कम करके देश में उत्पादित वस्तुओं के महत्व को बढ़ाने एवं विदेशी व्यापार की निर्भरता को कम करने तथा साथ ही देश–प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का सर्वोत्तम प्रयास है। मेक इन इंडिया के माध्यम से केवल देश को उत्पादन को तीव्र गति देना नहीं बल्कि उत्पादित वस्तुओं को एक बड़े बाजार एवं क्रेताओं को उपलब्ध कराना है जैसा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 25 सितम्बर 2014 से शुरू किया गया और देश की अर्थव्यस्था एवं व्यापार को विश्व बाजार में स्थापित करने एवं एक बड़े रोजगार का सृजन करना विशेष लक्ष्य रहा है।

परिचय :–

मेक इन इंडिया भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने की बहुत ही बड़ी पहल है जो 25 सितम्बर 2014 में पिछले सात वर्ष पहले लागू की गई। और आज विस्तृत दौर पर शुरूआत 2020 में हुई। मेक इन इंडिया को भारत के अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार बदलाव बना है उस बदलाव में एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढाना है एट द सेम टाइम उसका सीधा लाभ भारत देश के विपणन चुनौतियों को कम करके युवाओं को रोजगार के रूप में मिले ताकि गरीब से गरीब परिवार के आर्थिक स्थिति में बदलाव आये वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसकी क्रय शक्ति बढ़े तो विनिर्माण की संख्या बढ़ेगी ''मैन्युफैक्चरिंग'', ग्रोथ बढ़ेगा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और फिर एक बाजार बढ़ेगा यह ऐसा चक्र है और इस चक्र के बढ़ने से यह एक शक्तिशाली कदम होगा। सात वर्षों से ज्यादा समय पहले शुरू हुये मके इन इंडिया को भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में बहुत अधिक बदलाव लाने की एक मजबूत पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस पहल के दो पक्ष है पहला सकल घरेलू उत्पाद यानि जी डी पी में विनिर्माण की हिस्सदेारी बढ़ाने से होने वाले लाभ को जोड़ा है। अभी यह हिस्सेदारी 17 फिशदी के आस–पास है जिससे की 25 फिशदी ले जाने का लक्ष्य है वही दूसरा पक्ष विनिर्माण के बढ़ने से होने वाले फायदे से जुड़ा है मसलन, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके (औसतन विनिर्माण में रोजगार के एक मौके बनते हैं तो सेवा क्षेत्र में 2–3 मौके बनते हैं) आमदनी में बढोत्तरी, उपभोग व उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़त विदेशी निवेश जुटाने में मदद (जिसका अनुकूल भारतीय रुपये पर देखने को मिलेगा) वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी, निर्यात व आयात आय में बढोत्तोरी आदि। मेक

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

इन इंडिया एक ऐसा पहल है जो निवेश को बढ़वा देने के साथ–साथ नवाचार को प्रोत्साहन देना, सर्वश्रेष्ठ संरचना का निर्माण करना और देश को डिजाइन, विनिर्माण और नौप्रवर्तन का हब केन्द्र बनाना है। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का विकास सरकार के प्रमुख प्राथमिकता बनी हुयी है। मेक इन इंडिया अपनी तरह की टवबंस वित सवबंस पहल की जिसने विश्व के समक्ष देश के विनिर्माण क्षेत्र को प्रस्तुत किया शुरू में इस पहल के तहत 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस पूरी योजना का शाखा सहयोग पूर्ण दृष्टिकोण जैसी सोच के आधार पर तैयार किया गया इसके लिये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के विभाग उद्योग संर्वधन और अन्तरिक व्यापार विभाव ने केन्द्रीय मंत्रियों भारत सरकार के सचिवों, राज्य सरकारों प्रमुख उद्योगपतियों और क्षेत्र विशेष के प्रमुख जानकारों के साथ मिलकर शुरूआती अवधारणा तैयार की। फिर दिसम्बर 2014 में सरकार और उद्योगपतियों की साझा कार्यशाला के जरिये तीन साल की कार्ययोजना तैयार की गई यहाँ पर और बात सामने आयी की जिस तरह सरकारी व निजी क्षेत्र की साझेदारी (App) बढ़े पैमाने पर बदलाव को लाकर अर्थव्यवस्था विपणन की चुनौतियों को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कम करके पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन किया जाय एवं देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं मजबूत किया जाय।

शोध प्रविधिः–

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक एवं वर्णात्मक प्रवृत्ति का है शोध पत्र मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीय आकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्य मुख्यतः आकड़ों के संग्रहित करने जबकि द्वितीयक तथ्य प्रकाशन, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं वाणिज्मिक पत्रिकाओं में छपे लेख प्राथमिक शोध कार्य आदि को आधार मानकर बनाया गया है।

अवलोकन :–

मध्यप्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत वस्तुओं का उत्पादन करके एक प्रदेश की बड़र संख्या में बेरोजगारी को कम करने का प्रयास विकया गया तथा बाजार को विस्तृत बनाने एवं विदेशी निवेश के उदार नियम से निवेश जुटाने की बात करके ज्यादा से ज्यादा उदार बनाने की जरूरत है। आज के इस आर्थिक परिवेश में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों व गतिविधियों में स्वतः अनुमोदन व्यवस्था के अन्तर्गत शत–प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में निवेश 100 प्रतिशत से नीचे है उनकी नियमित समीक्षा की जाती है और नियमों में बदलाव किया जाता है। म.प्र. राज्य सहकारी विपणल संत्र के अपने गोदाम है जहाँ वैज्ञाकि तकलीक से भण्डारण की सुविधा बनायी गयी है वैज्ञानिक ढ़ंग से भण्डारण करते हुए अपने गाहको को संतुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपणन में परिवहन की एकत बहुत ही बड़ी भूमिका होती है जिससे म.प्र. में सड़कों का दीर्घकालीन सुविधायुक्त निर्माण करके व्यापार को बढ़नें में महती भूमिका निभायी गयी है। इस सबका नतीजा है कि महामारी के बीच भी कारोबारी वर्ष 2020–21 के दौरान 8194 अरब डॉलर की विदेशी निवेश भारत में आया है। और बाजार के जोखिम को कम करके बाजार की बदलती स्थितियों को बैंकों ने भी अनुमान लगाकर विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के लाभ को उठाया है। राज्यों में औद्योगिक और कारोबारी माहौल सुधारने के लिए व्यापक सुधार कार्यक्रम की शुरूआत हुई है। इसके तहत कारोबारी सुगमता के मामले में राज्यों और कन्द्रशासित प्रदेशो की रैकिंग की जाती है जिसकी बदौलत राज्यों के बीच अपने क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। चार वर्षों से यह बैकिंग जारी की जा रही है। नीतिगत और जमीनी स्तर पर राज्यों और केन्द्र के स्तर पर पहल का नतीजा है कि भारत जहाँ 2014 में विश्व बैंक की करोबारी सुगमता (Ease of doing Business) रैकिंग में 142वें स्थान पर था, 2020 में 63वें स्थान पर आ गया है इससे यह पाया गया कि गित वर्षो में विपणन की नीतियों में पर्याप्त मात्रा में सुधार होने से विश्व बैंक की रैकिंग में सुधार हुआ जो वाणिज्यिक क्षेत्र को अधिक मजबूती प्रदान करके आने वाले वर्षों में व्यापारिक गतिविधियों का

विश्व में एक अलग स्थान प्रदान करायगी। अब Make in India अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और अब 27 क्षेत्र (देखें तालिका–1) इसके दायरे में हैं जिसमें से 15 विनिर्माण और 12 सेवाक्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

तालिका क्रमांक डांम पद प्दकपं में शामिल क्षेत्र

क्र.	विनिर्माण (Manutacturing)	सेवा (Service)
1.	ऑटोमोटिव व आटो कंपोनेंट्स।	मैडिकल वैल्यू ट्रैवल।
2.	एयोस्पेस व रक्षा।	सुचना प्रौगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
3.	जैव प्रौद्योगिकी।	पर्यटन व लॉजिस्टिक सेवाएँ
4.	फार्मास्यूटिकल्स व मेडिकल डिवाइसेस।	अडियो विजुअल।
5.	कपडा व परिधान।	परिवहन और लाजिस्टिक सेवाएँ
6.	कैपिटल गुड्स (ब्ंचपजंस हववके)	लेखा और वित्त सेवा (Accounl and finance service)
7.	इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एड मैन्युफेक्चरिंग	संचार सेवाएँ
8.	रसायन व पेट्रोरसायन।	कानूनी सेवाएँ
9.	खाद्य प्रसंस्करण।	शिक्षा सेवाएँ
10.	चमड़ा और फुटवेयर।	वित्तीय सेवाएँ
11.	जहाजरानी	पर्यावरण सेवाएँ
12.	रत्न व आभूषण।	निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएँ
13.	रेल (Railway)	
14.	निर्माण (formation)	
15.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	

जैसा कि तालिका 1 से स्पष्ट हो जाता है कि विपणन में पयाप्त सुधार मेक इन इंडिया के कारण हुआ क्योंकि इसमें निर्माण क्षेत्र से लेकर 12 सेवा क्षेत्रों का शामिल होना अपने आप में व्यापारिक गतिविधियों और विपणन में एक बहुत बड़ा सुधार है। इसे सरकारी खरीद को भी प्राथमिकता दी गई जिसमें से 50 लाख रुपये या उससे कम राशि की खरीद के लिए और नोडल मंत्रालय का यह मत है कि खरीद से सम्बधित क्षेत्र में पर्याप्त घरेलू और बरेलू प्रतिस्पर्धा है। ऐसे मामलों में केवल घरेलू आपूर्तिकर्त्ता पात्र होंगें।

निष्कर्ष :–

मध्यप्रदेश में विपणन की चुनौतियों को कम करने से मेक इन इंडिया का व्यापक प्रभाव देखने को मिला है जैसा कि मध्यप्रदेश में राज्य विपणन संघ के द्वारा मुख्य रूप से कृषि विपणन का केन्द्र के रूप में विकसित किया गया साथ ही मेक इन इंडिया में शामिल क्षेत्र के द्वारा आत्मनिर्भरता की बात इस घरेलू बाजार माँग पूरी करने के साथ ही खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होकर विश्व बाजार में पैठ बनाने की लगातार कोशिशों के साथ जुड़ जाती है। आइये एक नजर डालते है कि सात वर्षों में कुछ खास क्षेत्रों की किस तरह प्रगति हुई है और आगे किस तरह संभावनाएँ बन रही है। जैसे ऑटोमोबाइल के विनिर्माण क्षेत्र में 35 फीसदी हिस्सेदारी के साथ–साथ दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के निर्माण में भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया यात्रीवाहन के मामले में चौथे स्थान पर है। इलेक्ट्रानिक वाहन के लिए एक खास व्यवस्था ई–अमृत की शुरूआत की गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रानिक वाहन को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश की गयी। फार्मास्यूटिकप्स एवं मेडिकल उद्योग का आकार 43 अरब डॉलर का है दवा उद्योग की विकास दर 7–8 फीसदी, मेडिकल डिवाइस उद्योग की विकास दर 15–16 फीसदी है। खाद्य प्रसंस्करण 2014–15 के दौरान सकल मूल्य संवर्धन (GVA) 134 लाख करोड़ रुपये का जो 2019–20 में 2.24 लाख करोड़ रुपये पहुच गया। रेल्वे में कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया 24 घण्टे के भीतर बगैर किसी प्रदूषण के पूरे कचरे का प्रसंस्करण हुआ। निवेश संवर्धन के लिये विशेष दल बनाया गया। Nationel sigal wihelow system बनाया विश्व बाजार में भारत की विपणन हिस्सेदारी एवं म.प्र. की हिस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। देश का जो उन्होंने (PM) 17 जनवरी 2022 को World Economic Fooam में संबोधन के दौरान बताया है। ''हम मेक इन इंडिया' मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना से आगे बढ़ रहें।''

संर्न्भ ग्रन्थ सूची :–

1. योजना पत्रिका, फरवरी, 2022
2. कुरूक्षेत्र पत्रिका फरवरी 2022
3. एस. एन. ला, भारतीय अर्थव्यवस्था